श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने जो प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा एटम बम बनाए जाने के बारे में उठाया मैं उसका समर्थन करता हूं। इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ता है और पाकिस्तान की सीमा पर आए दिन तनाव जो रहता है वह भारत के लिए चिन्ता का विषय है । मैं आशा करता हूं कि एटम बम का खतरा सारी दुनियां से खत्म हो। एक तरफ सारी दुनियां हथियारों पर रोक लगा रही है दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश एटम बम बना रहा है यह भारत के लिए ही नहीं सारे एशिया के लिए खतरा है। इस प्रकार सरकार को गम्भीरता से चिन्ता करनी चाहिए । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI IAGESH DESAI): The House now stands adjourned for lunch and will meet again at 2.45 P.M.

The House then adjourned for lunch at forty-seven minutes past one of the clock.

The House reassembled, after lunch. at forty six minutes past two of the clock. The Vice-Chairman (Shri .. Jaffesh D«sai) in the Chair.

SHORT DURATION DISCUSSION

Problems and Difficulties of Farming Community in the Country. .Contd.

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय सदस्यों ने किसानों की समस्याओं के बारे में बहुत ही गहरी रुचि दिखायी। जो भी उनकी समस्याएं थीं, बहुत तफसील के साथ उन्होंने सारी बातों का वर्णन यहां पर किया । मैं इस बात के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं । दोनों ही साइडस से सभी सदस्यों ने बहुत सी बातें ऐसी कहीं जो वजनदार थी । कुछ सदस्यों ने इन बातों को थोड़ा सा पोलिटिकल रंग देने की कोशिश भी की, मैं उनके बारे में आगे चलकर जवाब दूंगा, लेकिन जिन भी महानुभावों ने इस डिबेट में हिस्सा लिया बहुत ही मूल्यवान बातें उन्होंने कहीं मैं उनका आदर करता हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है । हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है । अगर देश का किसान ठीक नहीं होगा, देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, देश के किसान की हालत अगर अच्छी नहीं होगी तो किसी भी वर्ग की हालत अच्छी नहीं हो सकती है । इस मूल्य की सारी की सारी अर्थव्यवस्था ही दरहम बरहम हो जायेगी । इसी बात को सामने रखकर जब देश आजाद हुआ था उस समय देश के महान नेताओं ने किसान के हित में बहुत बड़ी बड़ी योजनायें बनायी । इस बात को महसूस किया कि किसान की हालत को बेहतर बनाना है और देश को अपने पांवों पर खड़ा करना है । जिस मुल्क में खाने के लिए अपना अनाज न हो उस मुल्क की प्रतिष्ठा दूसरे मुल्कों के सामने बहुत कम हो जाती है । जब दूसरे के सामने किसी व्यक्ति को मांगने जाना पड़ता है तो उससे उस आदमी के वकार को बड़ा धक्का लगता है । हमारे देश के महान नेता फांसी पर चढ़ना आसान काम समझते थे लेकिन सिर झुकाना उनके लिए बड़ा भारी मुश्किल काम था । हमारे उन नेताओं को दूसरे मुल्कों में जाकर अनाज के लिए झोली पसारनी पड़ती थी, भिखारी की शक्ल में खड़े होकर अनाज मांगना पड़ता था । लेकिन हमारे मुल्क के बहादुर नेताओं ने किसान के हित में ऐसी नीतियां बनायी कि जिनका परिणाम है कि किसान भी आज अपने पांव पर खड़े हुए हैं और हम भी आत्म सम्मान के साथ दूसरे मुल्कों के सामने छाती तानकर खड़े हुए हैं । आप जानते हैं जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे मुल्क में कुल पैदावार 50 मिलियन टन होती थी । आज 50 मिलियन टन से बढ़ कर हमने 152 मिलियन टन को टच किया है, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है । तीन गुना उत्पादन अकेले अनाज का होना बहुत बड़ी बात है । इसी तरह से आप सिचाई के साधनो के बारे में जानते है । जब देश आजाद हुआ था उस समय सारे मुल्क में . . . कुल अढ़ाई करोड़ हैक्टर में सिचाई होती थी, आज तकरीबन छह करोड़ हैक्टर में सिचाई होती है ।

इसी तरह से आप जानते हैं कि जब यह देश आजाद हुआ था, इस मुल्क में एक भी एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी नहीं थी, आज 26 एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटीज, कितने अनुसन्धान हैं, कितनी खोज की गई है अच्छे सीड और बीज पैदा करने के लिए, कितने खाद के कारखाने हैं, ट्रैक्टर्स के कारखाने हैं, बिजली के बड़े-बड़े तापघर, कितने बड़े-बड़े डैम इस मुल्क में बने ताकि किसान को समय पर पानी दिया जाए, खेत के ट्यूबवैल के लिए बिजली दी जाए, अच्छा बीज दिया जाए, अच्छा खाद दिया जाए और पूरी जानकारी किसान को दी जाए ।

यह सारी बातें मुल्क के सामने आप देखते हैं और उसी का नतीजा है कि आज इतना उत्पादन हमारा किसान कर पाया है और जितनी चीजें हमने की हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि साहब किसान की जरा और भी सहायता करनी चाहिये ।

पं० जवाहरलाल नेहरू ने जब इस आधुनिक भारत की आधारशिला रखी थी, तो सब से पहले उन्होंने किसान के बारे में सोचा था और अपनी वसीयत में लिखा है पंडित जी ने कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियां तथा मेरे शरीर की भस्मी को भी किसान के खेत में छिड़कना । इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। उनके दिल में किसान के लिए कितनी तड़प, कितनी लग्न थी, किसान को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने इस देश में क्या नहीं किया ।

आप जानते हैं कि अगर सारी बातों का हम हिसाब लगायें कि जो हम किसान पर खर्च करते हैं और उस के मुकाबले हमको इनकम क्या होती है, तो आप खुद महसूस करेंगे कि पानी की एक बूंद एक रुपए में आकर पड़ती है जब नहर बना करके, डैम बना करके उसको खेत में पहुंचाते हैं, और उसके लिए हम चार्ज क्या करते हैं । बहुत मामूली---यह इरिगेशन का हिसाब है ।

उपसभाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि बिजली जो आज घर में 80.22 पैसे प्रति यूनिट पड़ती है यानी 80 पैसे लगा लें किसान को बिजली हम किस भाव पर देते हैं ? 17.62 पैसे प्रति यूनिट पर या 18 पैसे प्रति यूनिट के भाव में हम किसान को बिजली देते हैं और सारे देश के अन्दर 1762 करोड़ रुपए का हर साल बिजली बोर्डस को घाटा सोता है, सिर्फ सब्सिडाइज करने की वजह से कि 80 पैसे प्रति यूनिट बिजली घर में पड़े और वह 18 पैसे प्रति यूनिट किसान को जाए : एवरेज कास्ट उसका जो है वह 18 पैसे यूनिट, 62 पैसे एक यूनिट बिजली में घाटा होता है ।

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : अफसरों से मिल कर बिजली की चोरी होती है, उससे घाटा होता है ।

श्री भजन लाल : वह भी हो सकता है। आप भी उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री रहे हैं, मैं जानता हूं विकल साहब---आप खुद जानते होंगे इस बात को---ठीक बात है कि बिजली की चोरी होती है । लाईन लासेज जो हैं वह भी तकरीबन 18--20 प्रतिशत होते हैं । वह अलग बात है।

श्री गुलाम रसूल मट्टू (जम्मू और कश्मीर) : वह अलग विभाग है ।

श्री भजन लाल : मैं आपको बता रहा हूं कि जो बिजली घर में पड़ती है वह इस भाव में पड़ती है । कम से कम नो-लास, नो-प्रोफिट तो कह ही सकता है आदमी देने के लिए, पर नहीं 62 पैसे यूनिट का घाटा खाकर के 1762 करोड़ रुपए का हर साल बिजली बोर्ड को किसान के लिए घाटा बर्दाश्त करना पड़ता है ।

इसी तरफ से आप जानते हैं कि खाद पर तीन हजार करोड़ रुपए की हर साल सब्सिडी दी जाती है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि साहब खाद पर सब्सिडी किसान को सीधी दी जानी चाहिये

[श्री भजन लाल]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीधी का कोई तरीका नहीं बनता । बहुत कोशिश इस मामले में की गई है कि किसान को सीधी सब्सिडी दें । अगर सीधी सब्सिडी देने की बात करते हैं तो बीच में बड़ी भारी करप्शन होने की संभावना रहती है । उसके घर तक सही सब्सिडी पहुंचानी बड़ी मुश्किल है । इसीलिए हमने कहा कि जहां से उत्पादन होता है, वहां से इसका सारा हिसाब लगा करके और कम कीमत पर किसान को सीधी खाद दे दी जाए और फैक्टरी को सब्सिडाइज करते हैं जहां से खाद बनती है । उसमें से हो सकता है कि कुछ फैक्टरी वाले अपने एकाउंट में खर्च ज्यादा दिखा देते होंगे । इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि थोड़ा बहुत जो फैक्टरी को सब्सिडाइज करते हैं, उसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करते होंगे, लेकिन फिर भी हमने उस को बड़ा चैक करने की कोशिश की ताकि उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो और सब्सीडाइज्ड करने की वजह से इस साल आप जानते हैं कि बजट में जो भाव कम करके पहले टोटल से मैं कह सकता हूं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में 12 हजार करोड़ रुपये की सब्सीडी अकेले खाद पर दी गई आपके सामने है । इसी तरह से जो किसान बैंकों से लोन लेता है उसका पहले 14 परसेंट होता था, फिर साढ़े बारह परसेंट किया और इस बार सवा ग्यारह व दस परसेंट किया है । तकरीबन दो सौ करोड़ रुपए का फायदा अकेले इस साल में बैंकों का सूद कम करने की वजह से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा है । फिर उसके बाद उप सभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि इसके मुनासिब भाव होने चाहिये और किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिये । यह बिल्कुल सही बात है कि किसान बहुत मेहनत करके अनाज पैदा करता है । आप जानते हैं जब सर्दी के महीने में जनवरी-फरवरी में खेत में जब किसान पानी देता है और जब ठंडे पानी में चलता है तो उसको पता नहीं चलता है कि उसके नीचे उसका पांव है भी या नहीं । जब बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में मई-जून के महीने में जब फसल को काट कर खलिहान में डाल कर जब गुहाई करता है तो पसीना चलता है चोटी से जूती पसीने में भर जाती है । क्योंकि मैंने भी छोटे किसान के घर में जन्म लिया है और मैं इस बात को जानता हूं । मैंने अपने हाथ से कटाई की है और दरांती अभी तक लगी हुई है । मैं जानता हूं कि किसान की क्या समस्या है। बड़ा कठिन काम है इसमें कोई दो रायें नहीं हैं , लेकिन आप जानते हैं उप सभाध्यक्ष महोदय कि इस देश के रथ के दो पहिये ऐसे हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है । अगर रथ का एक पहिया बहुत आगें चला जाए और दूसरे पहिये को खाने को भी नहीं मिले तो बहुत मुश्किल आ सकती है । आप जानते हैं, इसी तरह से जो गरीब आदमी खाने वाला है जिसने मोल लेकर खाना है, जिसने मजदूरी करके सड़क पर मिट्टी डाल कर खाना है उस आदमी का ध्यान भी सरकार को रखना पड़ता है । छोटे सरकारी कर्मचारी और दूसरे अधिकारी हैं उनका भी सरकार को ध्यान रखना पड़ता है और उसके साथ-साथ बहुत ज्यादा भाव बढ़ाना किसान के हित में भी नहीं है । बहुत से भाई कहेंगे कि भजन लाल जी यह क्या बात कहता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका सारा प्रभाव किसान पर आकर पड़ता है । आज हम एक तरफ कह दें गन्ने का भाव सौ रुपये क्विंटल होना चाहिये तो क्या फिर किसान को चीनी दो रुपए किलो मिल जायेगी ? एक तरफ कपास की कीमत एक हजार रुपए क्विंटल होनी चाहिये तो क्या किसान को दो रुपए गज कपड़ा मिल जाएगा ? किसान को बेचनी पड़ती हैं मुश्किल से 7 चीजें और और 110 चीजें खरीदनी पड़ती हैं । सुई से लेकर ट्रैक्टर तक किसान को लेने पड़ते हैं । उसका सारा प्रभाव आप जानते हैं कि किस पर पड़ता है । फिर देश की जितनी भी बाकी महंगाई का हिसाब है उस हिसाब से कितने कर्मचारियों को जब वेतन का हिसाब-किताब देना पड़ता है और टी.ए., डी.ए. सारा हिसाब लगायें तो देश की सारी अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है । इसलिए इन सारी बातों का हिसाब लगा करके भाव तय किए जाते

हैं और भाव तय करते समय किसान को बाकायदा लाभकारी मूल्य देते हैं । लाभकारी मूल्य के साथ-साथ आप देखते हैं आज से 15 साल पहले जब भारत सरकार की तरफ से सपोर्ट प्राइस तय नहीं थी उस समय किसान की क्या हालत थी। मंडियों में जब किसान अनाज लेकर जाता था हफ्ता-हफ्ता दस-दस दिन वह पड़ा सड़ा करता था और उसे कोई पूछने वाला नहीं था । मनमर्जी के भाव में दुकानदार, व्यापारी और बिजनेसमैन उसे खरीदता था । उसने जो भाव मुंह से कह दिया उसी भाव में लेता था । इसी बात को लेकर इस देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने महसूस किया कि किसान की अगर यह हालत हुई तो किसान *पिस जाएगा* । इसलिए सपोर्ट प्राइस यानी कम से कम भाव में तो यह बिकना ही चाहिये और इसके लिए सपोर्ट प्राइस तय की गई ताकि किसान मरे नहीं और वह जिंदा रह सके तथा उसको मुनासिब भाव मिल जाये । इससे पहले किसान की बहुत बुरी हालत थी । यह मैं कहता हूं कि आज अगर यह भारत सरकार सपोर्ट प्राइस तय नहीं करे तो जिस भाव पर किसान की जिंस आज बिकती है इस भाव में कोई लेने वाला नहीं है । अभी मैं बताता हूं, बहुत से भाई राजस्थान और गुजरात से ताल्लुक रखने वाले हैं ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (हरियाणा): वह गेहूं जो है, चौधरी साहब, वह जो सपोर्ट प्राइस में बिका आज पौने तीन सौ रुपये में . . . (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल : वह मैं आपको बताऊंगा . . . (**व्यवधान**)

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : वह कैसे हो गया उपभोक्ता और सरकारी मुलाजिम आज क्या खा रहे हैं जो सौ रुपए भाव गेहूं का मिलता है वह तो 175 रुपए या 176 रुपए यानी प्रोक्योरमेंट प्राइस थी उसके उपर बिका था ? इसको क्लेरीफाई कर दीजिए कि रेमुनेटिव प्राइस किसको कहां मिली ?

3.00 P.M.

श्री भजन लाल : मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि किसान इस भाव में ही बेचे, किसान पर कोई पाबंदी नहीं है । यह जो सपोर्ट प्राइस है, उसकी मदद के लिए है और उसमें प्रोफिट है । सारे मुल्क में वह फसल कहीं ले जाना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं है, उसे कोई मनाही नहीं है । वह सारे मुल्क में कहीं ले जाकर बेच सकता है, जहां उसको फालतू पैसा मिलता हो। यह तो उसकी मदद के लिए है सपोर्ट प्राइस ।

श्री राम चन्द्र विकल: यू० पी० के किसान का गल्ला दिल्ली में नहीं आता, न पलवल के किसान का आता है। यह आपको जानकारी है या नहीं ? नहीं आने देते दिल्ली में ।

श्री भजन लाल : मैं आपको बताऊं, दिल्ली में लाने पर कोई पाबंदी नहीं है, गवर्नमेंट की ओर से कोई पाबंदी नहीं है। इसमें क्या है कि कई स्टेट, एकाध स्टेट मिसाल के तौर पर पंजाब को ले लें, जिनको प्रोक्योर करना है, राइस प्रोक्योर करना है तो वह भी प्रोक्योर करने के हिसाब से थोड़ा-बहुत चैक करते हैं ताकि उन्होंने प्रोक्योरमेंट का जो लक्ष्य रखा है, पूरा हो जाये । इसमें चेक करने की बात इसलिए है कि आपने गांव में सीधी पेड्डी ली, मिल में उसका चावल बनाया और सीधे बिना किसी एकाउन्ट में दिखाए मंडी में ले जाने की कोशिश करते हैं।. . . (**व्यवधान**) . . .

नहीं, किसान के घर में प्रोक्योरमेंट जाता नहीं, यही तो मुश्किल है । वह लेता है मिल वाला और तभी जाता है प्रोक्योरमेंट में । लेकिन किसान का जो लेता है, वह सारी बातें सोचकर लेता है और किसान भी सोचकर बेचता है । किसान भी आज इतना भोला नहीं रहा, वह भी इस बात को समझता है । लेकिन समस्या छोटे किसान की इसके बीच में है, छोटे किसान के साथ भी कुछ ज्यादती है कि छोटे किसान का पूरा ट्रक होता नहीं और कई दफा उसको अपने गांव में ही बेचना पड़ता

[श्री भजनलाल]

है। लेकिन भारत-सरकार की पूरी मंशा हमेशा यह रही है किसान के हित में, कि किसान को लाभकारी मूल्य मिले। एक-एक बात का हिसाब लगाकर हमने किसान को कीमत देने की कोशिश की है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमेशा यह शिकायत रही बहुत से माननीय सदस्यों की, कि यह जो एग्रीकल्चर-कमीशन बना है, इसमें किसानों के नुमाइंदे नहीं है। हमने इस बार इसमें तीन किसानों के नुमाइन्दे रखे हैं ताकि एक-एक बात की तह में वे जायें और सारी बातों की तह में जाकर भाव तय करें। वे जमीन का हिसाब लगाते हैं, अगर जमीन पट्टे पर ले रखी है तो पट्टे के हिसाब से लगाते हैं, पानी का, बीज का, खाद का, स्प्रे का, कटाई-बिवाई से लेकर के कितनी बार जोतना पड़ेगा, सारी चीजों का हिसाब लगाकर और उसमें प्रोफिट लगाकर आज भाव तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे ही हम करते हैं कि जो मर्जी हुआ, सो भाव तय कर दिया। इसके बाद भी किसान को छूट है कि जहां उसकी मर्जी हो वहां ले जाकर बेच सकता है। क्योंकि पिछले दो-तीन साल से सूखा पड़ता रहा और सूखे की वजह से दिक्कत जरूर आई। इसमें कोई दो रायें नहीं कि उस समय भाव बढ़े। जैसे आज 145/- रुपए बाजरे का भाव तय किया है, यही बाजरा छह महीने पहले 300/- रुपए में मिलता नहीं था क्योंकि सूखे की वजह से पैदावार नहीं थी मुल्क में। पैदावार न होने से 300/- रुपए के भाव में लोगों को खाना पड़ता था। अब यही बाजरा मंडियों में कुछ समय पहले 110/- रुपए भी बिकने लगा था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी लोक सभा से मैं आया। वहां भी इस पर डिसकस हो रहा है। राजस्थान के माननीय सदस्य रामसिंह यादव जी ने अभी कहा कि कई जगह अभी भी आपके प्रोक्योरमेंट वाले नहीं पहुंचे हैं, कई जगह खरीद शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से 125/- रुपए के भाव बिक रहा है। सपोर्ट प्राइस का मतलब यही है कि किसान को अच्छा भाव मिले और वह भाव देने की हमने कोशिश की है। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहस को शुरू करते हुए वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा, रामनरेश यादव जी ने कहा कि उत्पादन में बड़ी भारी गिरावट आ गई है मैं इस देश के किसानों, को बधाई देना चाहता हूं कि इतना भयंकर सूखा पड़ने के बावजूद भी हमारे देश का उत्पादन 4 परसेंट से ज्यादा नहीं गिरा। अमरीका में एक साल सूखा पड़ा, वहां इतनी महंगाई ऊंची बढ़ी कि कहने की बात नहीं है। लेकिन यहां चार साल सूखा पड़ने के बावजूद भी एक आदमी को भी देश में आज की सरकार ने भूख से नहीं मरने दिया। आपको 1956 के अकाल की याद होगी जिसमें कि भूख के कारण लाखों-लाख आदमी सड़कों पर मरे हुए देखे गए लेकिन पिछले दिनों इतने भीषण सूखे के बावजूद किसानों ने बड़ी मेहनत कर के अनाज की पैदावार को स्थिर रखा और कम नहीं होने दिया। पता नहीं कहां के आंकड़े दिए हैं, यहां 138 से 170 अर्थात् 32 मिलियन टन अनाज फालतू हर हालत में पैदा होगा 32 का 33 हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। हमने सारी बात का जायजा लिया है। 138 से 177 का हिसाब लगाए तो 23 परसेंट ग्रोथ रेट बैठती है। 152 से 180 का हिसाब लगाए तो भी 12 परसेंट बैठती है। लेकिन हमें इससे तसल्ली नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश): मंत्री जी 170 हो तो जाने दो।

श्री भजन लाल: इसमें कोई शक नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: ईश्वर करे हो जाए।

श्री भजन लाल: हम भी ईश्वर को मानते हैं।

श्री गुलाम रसूल भट्टू: इंसाल्लाह 75 हो जाय।

श्री भजन लाल: हर हालत में अगले साल 75 होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि देश के किसान की हर हाल में हर तरह से सहायता करनी है और कर रहे हैं। जैसेकि किसान को लाभकारी मूल्य देने के बारे में और जो भी किसान की जरूरियात है उन को हर तरह से, हर समय पूरा करने की कोशिश सरकार कर रही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनके बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे पहले वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा कि मूल्य निर्धारण की पद्धति पर्याप्त नहीं है। किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मैंने जैसाकि आपकी सेवा में अर्ज किया कि सारी बातों का हिसाब लगाने के बाद हम भाव तय करते हैं और किसान को लाभकारी मूल्य देते हैं। उत्पादन में हानि और लाभ दोनों का हिसाब लगाते हैं। वह अपने खेत में जो अनाज बोएगा तो क्या खर्च आएगा और उसको जो भाव दिया है और उत्पादन के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा—इन दोनों बातों का हिसाब लगाकर बाद में लाभकारी मूल्य सरकार तय करती है। इससे माननीय सदस्यों को तसल्ली होनी चाहिए।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक: उसका मुनाफा कितना परसेंट लगाओगे?

श्री भजन लाल: अभी बताता हूं।

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH (Maharashtra): Sir, what I mean to say is that while fixing the prices for the agricultural produce by the Agricultural Prices Commission, what is the price taken into account for a cartload of manure, cowdung or chemical manure? Then, again what are the wages they are counting for hired labour? Tot the best of my knowledge, they are Rs. 10 for a cartload of manure. But how is it possible?

श्री भजन लाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, किसान के खुद के काम का, लेबर का हिसाब, उसके ऊंट और बैल का हिसाब, कितनी बार खेत को बोना पड़ेगा—इन सारी बातों का हिसाब लगाते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): उनका यह कहना है कि वह आपने बहुत कम रखा है।

श्री भजन लाल: उनका कहना है कि वह मैनुअल बहुत पुराना है, ठीक होना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं कि वह मेरी चर्चा करते हैं, लेकिन मैंने जो मुद्दे उठाए हैं वे उनकी भी चर्चा करें। किसान 13.7 फीसदी घाटे में था प्राइस रिसीव्ड एंड प्राइस पेड के हिसाब से, वर्ष 1986-87 में 18.1 फीसदी रहा और आप कह रहे है कि हम लाभकारी मूल्य दे रहे हैं।

श्री भजन लाल: मैं इसी पाइंट पर आने वाला था। लेबर का और सारी बातों का हिसाब लगाकर बाद में भाव तय करते हैं। यह हो सकता है लेबर का 18 रु० हो उसका 12 या 15 लगा दिया होगा। लेबर तो 18 रुपए में काम करेगी, घर का आदमी अगर काम करेगा तो दो घंटे करके फिर छोड़कर और काम में लग जाएगा या घर आ जाएगा। ...(**व्यवधान**)... आप मेरी बात सुन तो लीजिए। आप मेरे फार्म को चलकर देखें। मैं कह सकता हूं कि अच्छे-से-अच्छे किसान की जो खेती है, उससे मेरी खेती अच्छी मिलेगी, हालांकि उसे देखने का मौका कम मिलता है।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : इसीलिए तो दाम आप सही नहीं तय कर पाते हैं। मान्यवर, आपके पास फार्म हैं, बड़ी खेती है।

श्री भजन लाल : बहुत बड़ी खेती तो किसी के पास भी नहीं है।

श्री ईश दत्त यादव : छोटा किसान किस मेहनत से पैदावार करता है, इसका आपको और सरकार को पता नहीं चल पाता।

श्री भजन लाल : आप तो जानते हैं इस बात को कि अगर किसान किसी का बैल भी मांगकर ले जाए एक दिन के लिए तो अपने बैल की तो 2 घंटे दोपहर में छुट्टी करेगा, पानी वानी पिलाएगा लेकिन उसकी छुट्टी नहीं करता है। जब उसकी बहुत आफत आ जाए, कोई आदमी मिले नहीं, फसल पककर नीचे गिरने वाली हो जाए तब तो वह रात को भी करेगा कि फसल बरबाद होने जा रही है। एक बात जो वर्मा जी ने कही बाकी चीजों की वृद्धि तो ज्यादा व्यापार में हुई है और किसान की वृद्धि कम है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि यह जो हिसाब लगाते हैं, सारे मुल्क का है लेकिन सारे मुल्क में पैदावार एक जैसी नहीं है। पंजाब में, हरियाणा में आप जाएं, पंजाब और हरियाणा के मुकाबले आसाम में नहीं, राजस्थान में नहीं, गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, आपके बहुत से प्रांतों में नहीं। उनके सारे अकाउंट जब मिलाते हैं तब तो ठीक बात है लेकिन साथ में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर उनका हिसाब लगाएं तब आप महसूस करेंगे कि वाकई उनका उत्पादन तमाम ज्यादा है, और अगर उनका हिसाब लगाएं तो एवरेज वाकई कम हो जाएगी क्योंकि उत्पादन का फर्क है इसलिए एवरेज कम बैठेगी। लेकिन जो मुल्क तरक्की करता है उस मुल्क में अगर उद्योग की ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी तो वह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर को कम्पीटिशन में लाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यह मामला। दो पहिए हैं देश के—देश की अर्थ-व्यवस्था उद्योग पर भी डिपेन्ड करती है, खेती पर भी डिपेन्ड करती है। उद्योग जब आगे बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी लेकिन उसके साथ में अगर खेती को कम्पीटिशन में लाया जाए तो यह बड़ा कठिन काम है, फिर तो मामला जमेगा ही नहीं। उसके साथ-साथ एक बात इन्होंने कही कि भारत में फसलों का उत्पादन अन्य देशों के मुकाबले में कम है। यह आप-की बात मैं मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्यों कम है इसकी गहराई में आप नहीं गए। दूसरे मुल्कों में जो खाद डालते हैं, दूसरे मुल्कों में 30 के० जी० से कम किसी मुल्क की भी एवरेज नहीं है। 300, 400, 450 के० जी० प्रति हैक्टेयर खाद डालते हैं लेकिन हमारे मुल्क में एवरेज क्या है, सिर्फ 51 है, और 51 तब है जब पंजाब की एवरेज 153 के० जी० प्रति हैक्टेयर, उत्तर प्रदेश की 79 के० जी० प्रति हैक्टेयर, हरियाणा की 79 के० जी० प्रति हैक्टेयर, तमिलनाडु की 105 के० जी० प्रति हैक्टेयर है, तब जाकर एवरेज बैठती है। अगर हम आसाम को ले लें तो 4 के० जी० खाद डालते हैं एक हैक्टेयर में। उड़ीसा में 20 के० जी०, मध्य प्रदेश में 20 के० जी०, राजस्थान में 16 के० जी० डालते हैं एक हैक्टेयर में और वहां 16 के० जी० और वहां 350, 400 के० जी०। आप तो जानते हैं कि जमीन, जैसे कोई आदमी नशई हो जाता है, नशा करने वाला पहले तो थोड़ी सी अफीम खाता है तो 5—4 साल बाद उसे खुराक और बढ़ानी पड़ेगी और आखिर में, 20 साल बाद उसे यह और बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कोई आदमी विस्की या शराब पीता है तो पहले तो एक पैग से शुरू करता है और बाद में आधी बोतल पर पहुंच जाता है और बाद में आधी बोतल भी जब तक गट-गट करके नहीं पीता तब तक उसे नशा नहीं होता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : बड़ा तजुर्बा है आपको ।

श्री भजन लाल : यह तजुर्बा मैंने आप जैसे बड़े-बुजुर्गों से ही कर रखा है क्योंकि आप जैसे बड़े बुजुर्ग ही बता देते हैं कभी-कभी कि भाई भजनलाल पहले एक-दो पैग से नशा हो जाता था लेकिन आजकल तो आधी बोतल में भी नहीं होता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : लेकिन मंत्री जी, जो चीज आप कह रहे हैं, वही चीज मैंने आपको लिखकर दी है कि खाद कम है, इसलिए पैदावार कम है...

श्री भजन लाल : मैं आपकी बात पर ही आ रहा था...

श्री रामनरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : आपने कहा कि किसान हमारे यहां का खाद कम इस्तेमाल करता है, अगर वह खाद इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वह भी चौपट हो जाएगी क्योंकि आपके पास सिंचाई के साधन नहीं है, बिजली किसानों को नहीं मिलती है, तो वह खाद कैसे इस्तेमाल करेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा : इतनी महंगी खाद वह कैसे खरीदेगा ? आपने जिन देशों की चर्चा की है उनकी परकैपिटा इनकम भी तो देखो ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी कम है क्योंकि खाद की कमी है....

श्री भजन लाल : महोदय, यह कहते हैं कि खाद डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा । अगर खाद डालेंगे तो उतना ही खर्चा आएगा, मजदूरी भी उतनी ही लगेगी, पानी भी उतना ही लगेगा तो उत्पादन डबल हो जाएगा । तो किसान की आमदनी में फर्क नहीं पड़ेगा ? इसलिए हमारा कहना यह है कि खाद कम डालना उत्पादन में कमी की निशानी है । लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पानी और बिजली की कमी है । आप जानते हैं कि बिजली का मसला स्टेट सब्जक्ट है और स्टेट वाले भी हमेशा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिजली किसानों को दी जाए । बहुत से प्रांतों में और खासकर, हरियाणा और पंजाब में जहां उत्पादन अधिक होता है, 40 परसेंट बिजली किसानों को दी जाती है । सारे देश में उसका औसत 18 प्रतिशत है क्योंकि कहीं तो बहुत थोड़ी इस्तेमाल होता है । लेकिन पंजाब और हरियाणा में 40 परसेंट बिजली किसानों को दी जाती है । इरिगेशन में भी आप जानते हैं कि जहां अच्छे साधन हैं सिंचाई के वहीं खाद डाली जा सकती है, जहां साधन नहीं हैं, वहां खाद नहीं डाल सकती । इसलिए हमने यह भी तय किया है और नई बीज नीति, सीड नीति बनाई है भारत सरकार ने ताकि जिस मुल्क से भी ज्यादा यील्ड वाला बीज हमें मिल सके वहां से लाकर हम पैदावार बढ़ा सकें, इसके लिए इस साल से हमने किसानों के हित के लिए नई बीज नीति लागू की है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : फोरेन सीडस के बारे में कुछ लोगों ने कहा था, इस पर आपकी नीति क्या है ?

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र) : डिबेट में जवाब दे रहे हैं या प्वाइंट में जवाब दे रहे हैं ?

श्री भजन लाल : जैसे आपने पूछा है, मैं उसी तरह जवाब दे रहा हूं, समय देंगे तो मैं पूरा जवाब दूंगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You can take your own time.

श्री भजन लाल : धन्यवाद । श्रीमन, रामनरेश यादव जी ने सबसे पहले कहा कि खेती की एक सीमा है और जोतें छोटी हो गई । आप जानते हैं कि इसमें दो राय नहीं हैं कि जोतें कुछ छोटी हुई हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि उत्पादन में उससे कमी हुई । जोतें छोटी करने के कारण भी

[श्री भजन लाल]

हैं। यह तो नहीं है कि जमींदारी प्रथा को हम उसी तरह चालू रखते और जो एक एक आदमी के पास दो दो हजार एकड़ जमीन रहती थी, वे जमीन लेकर बैठे रहते तो इतना उत्पादन नहीं हो सकता। जोतें छोटी होने की वजह से किसानों की लगन और मेहनत की वजह से उसने छोटी जोतों से अधिक उत्पादन किया। उसको पता है कि वह बच्चों की पढ़ाई कैसे करेगा, उनकी शादी ब्याह कैसे करेगा, मकान कैसे बनाएगा, यदि उत्पादन नहीं बढ़ा या उसकी आमदनी नहीं बढ़ी तो? आपने देखा कि जिनके पास हजार दो हजार एकड़ जमीन होती थी वह बंजर पड़ी रहती थी। इसी बात को ध्यान में रखकर लेंड सीलिंग ऐक्ट बनाया गया ताकि गरीब आदमी जो भूखा सोता है, जिसके पास कमाने के लिए धरती एक फूट भी नहीं है उसको जमीन दी जाए। लेंड सीलिंग ऐक्ट लागू करके, जमींदारी प्रथा को खत्म करके उस आदमी को जो जमीन पर काश्त करता था, उनको मालिक बनाया ताकि वह जमीन को काबिज कर सके और उत्पादन बढ़ाए।

श्री राम नरेश यादव: मैंने यह कहा था कि किसानों की जोत भी कम हो जाएगी...

SHRI DARBARA SINGH (Punjab): Sir, I would request you to allow us to put questions after he finishes his speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl 1AGESH DESAI): Let us see.

SHRI DARBARA SINGH: I requesl you to allow us to put certain questions after the close of his speech.

श्री भजन लाल: सारी बातें इसमें हो आ जायेंगी। दूसरी बात आपने उत्पादन के बारे में कही। हमने जो लक्ष्य रखा है हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। जैसा आपने कहा कि देश के अंदर सिंचाई के साधन कम है, सिंचाई की जमीन कम है, यह बात हम मानते हैं। देश में 30 परसेंट धरती सिंचाई के नीचे है और 70 परसेंट सिंचाई के नीचे नहीं है। उसके लिए कई प्रोग्राम बने। मैं इस राय का हूं कि सारे देश के लिए एक नेशनल ग्रिड बनना चाहिए। सारे देश की बिजली के लिए नेशनल ग्रिड बनना चाहिए ताकि जहां पानी की आवश्यकता हो वहां पानी पहुंच सके। जहां पानी विनाश करता है वहां से पानी दूसरी जगह पहुंचाया जाए। ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, कावेरी है ये जितनी नदियां हैं इन सब का पानी इकट्ठा करके डेम बनाकर जहां पानी चाहिए वहां पानी पहुंचाया जाए और जहां बिजली की जरूरत हो वहां बिजली पहुंचाई जाये। लेकिन यह काम आसान नहीं है। इसके लिए बड़े साधनों की जरूरत है, बहुत बड़े धन की आवश्यकता है इतना बड़ा धन एक साथ होना बड़ा कठिन है। इसके बावजूद भी हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा एरिया सिंचाई के नीचे ला सकें। इसके लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं।

इसी तरह से आपने कहा कि खेतिहर मजदूरों को भी उनका पूरा हक मिलना चाहिए। आप जानते हैं बहुत सी जगहों पर खेतिहर मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेज एक्ट बना हुआ है कि खेत में काम करने वाले मजदूर को कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए। मैं हरियाणा की ही बात बताता हूं कि वहां पर 19.25 पैसे मिनिमम वेज रखा हुआ है। चाहे कोई मजदूर सड़क पर काम करता है या खेत में काम करता है इससे कम किसी को नहीं दिया जा सकता। इसके साथ-साथ बड़ी मुश्किल यह है कि जो बड़े किसान हैं वह कुछ शोषण करते हैं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक: किसान तो दे रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री वाले नहीं दे रहे हैं मिनिमम वेज।

श्री भजन लाल: उनको मिनिमम वेज देना चाहिए और उनको लेना चाहिए।

अगर कोई कुछ नहीं कहता तो भारत सरकार क्या करे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कई जमींदार ऐसा करते हैं कि जो लेबर उनके यहां काम करती है उसको उसका पांचवां या छठा हिस्सा देते हैं। जमीन किसान की है, खेत किसान का है, पानी किसान का है, बीज किसान का है, बिजली किसान की है लेकिन उसमें काम करने के लिए उसे पांचवा या छठा हिस्सा मिलता है। कई बार यह देखने में आया है कि ओले पड़ जाते हैं जिससे उनकी फसल खराब हो जाती है। लेकिन यह देखा गया है कि इसका मुआवजा तो वह पूरा ले लेते हैं परन्तु लेबरर को उसका हिस्सा नहीं देते। बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है उसका मुआवजा तो वह पूरा वसूल कर लेते हैं लेकिन उसका हिस्सा उसको नहीं मिल पाता। ऐसी शिकायतें मिली हैं। इसके लिए हमने कहा स्टेट्स गवर्नमेंट को कि जो गरीब आदमी है अगर उसको पांचवां या छठा हिस्सा मिलना है तो वह उसे मिलना चाहिए। यदि मुआवज का पूरा पैसा नहीं मिला है, कम मिला है तो उसी हिसाब से उसको भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। भारत सरकार इन खेतिहार मजदूरों का पूरा ध्यान रखती है।

इसके साथ-साथ यादव जी ने यह कहा कि सरकार बहुत सा सामान बाहर से मंगाती है। मैं आपका बताना चाहता हूं कि बाहर से मंगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले तीन-चार साल सूखा पड़ गया। थोड़ा बहुत ही हमने बाहर से मंगाया। सूखा पड़ने से पहले हमारे पास इतना सरप्लस हो गया था कि अनाज रखने के लिए जगह नहीं थी। आपने देखा होगा कि कितने ऊंचे-ऊंचे बोरे के ढेर लगा कर रखे जाते थे बाहर। उनके ऊपर तिरपाल ढक दी जाती थी ताकि खराब न हो फिर भी काफी अनाज खराब हो जाता था।

एक बात और इन्होंने कही कि यहां पर भाड़े की रैली की गयी। वह मुख्य मंत्री रहे हैं वह अपना जमाना भूल जाते हैं। जब चौधरी चरण सिंह की रैली यहां पर हुई थी, तब आप यू०पी० में मुख्य मंत्री थे और उधर चौधरी देवी लाल थे। जो यहां पर इकट्ठे हुए थे तो क्या मैं उनको भाड़े का कहूं या अपने आप आये हुए कहूं? उस रैली के दस साल बाद भी चौधरी चरण सिंह जिंदा रहे और जन्म दिन भी हर साल 23 दिसम्बर को आता रहा लेकिन कभी भी पांच हजार से ज्यादा यहां दिल्ली में इकट्ठे होते दिखाई नहीं दिये। भाड़े की रैली उसको कही जा सकती है।

इसके बाद देशमुख जी ने फिजूलखर्जी के बारे में कहा। उन्होंने कहा किसानों का शोषण हो रहा है, किसान बड़े परेशान हैं। लेंड सीलिंग एक्ट के बारे में कहा कि वह पूरी तरह से लागू नहीं है। देहात में लागू हो गया है लेकिन अरबन के लिए कानून बना नहीं, यहां पर भी कानून बन कर लागू होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : उन्होंने कहा है कि अर्बन लैण्ड सीलिंग के लागू होने से जो काश्तकार है, जो पेराफेरी में रहता है उसकी जमीन इसमें आ जाती है तो उनको कम पैसा मिलता है। यही उन्होंने कहा है।

श्री भजन लाल : उन्होंने दूसरी बात यह भी कही कि जो माइनर बच्चे हैं उनको भी यूनिट मानते हैं, लेकिन बालिग को भी यूनिट मानते हैं। यह लैण्ड सीलिंग एक्ट में है और इसमें कोई दो राय नहीं हैं। बालिग को यूनिट माना गया है। अगर सारे बच्चों को, अगर वे दो साल के या दो महीने के या चार महीने के हों, उनको भी मना जाय तो मुश्किल हो जाएगी। सारे रूक में 70 लाख एकड़ जमीन सरप्लसा निकली है और इस 70 लाख एकड़ में से 45 लाख एकड़ जमीन लोगों में बांटी गई है। 70 में से 25 लाख एकड़ जमीन के मामले अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आदलतों में 10–15 साल तक केस चलता है और कोई फैसला नहीं हो

[श्री भजन लाल]

पाता है। अगर अदालत बीच में आ जाती है तो सरकार कुछ नहीं कर पाती है।

जमीन के बारे में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जो आश्वासन देती है उनको पूरा नहीं करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो आश्वासन देती है उनको पूरा करती है। साइस की सप्लाई के बारे में स्टेट्स ने जो मांग की उसको हमने हमेशा पूरा करने की कोशिश की है और उनकी डिमान्ड को पूरा किया है। एक बार एक डिमान्ड में थोड़ी कमी रही और वह बिहार की शिकायत थी। इसलिए हमने उनको अच्छा गेहूं दिया, यद्यपि वह सर्टिफाइड नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उनके लिए कमी नहीं आने दी और हमने उनसे कहा कि जहां भी बढ़िया गेहूं मिल सकता है, वह हम उनको दे सकते हैं। इसके साथ-साथ एक बात उन्होंने यह भी कही कि किसानों को मुआवजे का ठीक पैसा नहीं मिलता है। यही बात विकल साहब ने भी कही कि वे लोग 10-10 साल तक पीछे पड़े रहते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि प्रधान मंत्री जी ने बकायदा फैसला किया और उसको एनाउन्स भी किया कि किसानों की जो उपजाऊ जमीन है, उसको एक्वायर नहीं किया जाएगा। लेकिन यह दूसरी बात है कि अगर कोई प्राजेक्ट उसी जगह पर बन सकती है दूसरी जगह पर नहीं बन सकती है तो मजबूरी में उस जमीन को एक्वायर किया जाय। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैं हरियाणा का सात साल तक मुख्य मंत्री रहा हूं। वहां पर हमने फैसला किया कि किसान की जमीन अगर एक्वायर की जाएगी तो मार्केट के रेट पर एक्वायर की जाएगी, बाजार भाव पर एक्वायर की जाएगी और किसान को पहले पैसा देकर बाद में उस पर कब्जा लिया जाएगा। ऐसा कानून हरियाणा प्रान्त में बना। उसको देखकर बहुत से अन्य प्रान्तों ने भी इसको लागू किया। मुझे याद है और ज्ञात भी है कि दूसरे राज्यों ने भी इसको चालू किया है और इसको होना भी चाहिए। इसके साथ-साथ आपने "गरीबी हटाओ" प्रोग्राम के बारे में भी कहा।

SHRI SHANKARRAO NARAYAN-RAO DESHMUKH: Excuse me, there is some confusion. What you have stated now regarding Haryana is perfectly justified and very correct. But that is not happening in all the States. Particularly in Maharashtra, the price of the land is laid down in the enactment itself. That is the whole trouble.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRi JAGESH DESAI): He will look into it.

श्री भजन लाल : ठीक है, इसको भी देख लेंगे। एक बात श्री हनुमंत राव जी ने कही कि सरकार किसानों की सहायता नहीं करती है और बड़े लोगों की सहायता करती है। मुश्किल यह है कि मुझे थोड़ा इस बात का अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सी०पी० एम० के लोग जब शहरों में जाते हैं तो कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है और जब देहातों में जाते हैं तो कहते हैं कि किसानों को कुछ नहीं मिलता है, उनका अनाज सस्ते भाव में बिक जाता है... (**व्यवधान**)। एक ही दिन में दो भाषाओं का ये प्रयोग करते हैं। एक ही मुंह से शहर में एक भाषा का प्रयोग करते हैं और देहातों में दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनको कम से कम एक भाषा तो बोलनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : इनकी पार्टी ही नहीं, सब पार्टियां ऐसा करती हैं।

श्री भजन लाल : सरकार दोनों बातों का ध्यान रखती है, खाने वाले का भी और बेचने वाले का भी।

SHRI MOTURU HANUMAN'IHA RAO (Andhra Pradesh): Out of 45 lakh acres, 12 lakh acres were distributed in West Bengal itself.

श्री भजन लाल : उन्होंने गन्ने के बारे में कहा कि आपने गन्ने का भाव

बहुत कम तय किया है । भारत सचकार ने गन्ने का भाव मिनिमम प्राइस पर तय किया है और उसको रिकवरी के साथ लिंक होता है । साढ़े आठ रिकवरी को पर 195 रुपया भारत सरकार ने तय किया है । इन्होंने कहा कि साहब आंध्र प्रदेश में 225 रुपया है । मैं कहता हूं कि 225 रुपये का सवाल नहीं है । इस समय गन्ने का भाव 32 रुपये से लेकर 35 रुपये तक है । मैं अगर यह कहूं, गन्ने के भाव या दूसरी चीजों के भाव, कोई पोलिटिकल बात कहूंगा तो थोड़ी सी इनको तकलीफ हो जावेगी । गन्ने की बात क ते हैं, महंगाई की बात करते हैं, दूसरी जिसों की बात करते हैं । बीच में थोड़े दिन इनका राज आया था । क्या हालत थी ? किसान की उस वक्त की हालत को दोहराऊंगा तो वीरेन्द्र वर्मा जी को तकलीफ हो जायेगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : बिल्कुल नहीं होगी ।

श्री भजन लाल : क्या हालत हो गई थी । जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो किसान का गन्ना 3.50 रुपये के भाव पर कोई लेने वाला नहीं था और किसान को खड़ा गन्ना खेतों में जलाना पड़ा । इंदिरा जी ... (व्यवधान) ... मैं मुख्य मंत्री था । मैंने हरियाणा में 15 रुपये से कम गन्ने के भाव नहीं होने दिये । मैंने वहां 15 रु ये से कम नहीं बिकने दिया ।... (व्यवधान) ...आप भी पड़ोस में मुख्य मंत्री थे । हमने उस समय 10 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया किसानों के लिये । मैंने मिल वालों से कहा कि 15 रुपया आपको लेना पड़ेगा । मिल वाले कहने लग कि बड़ा नुकसान होगा । मैंने कहा कि अगर नुकसान होगा तो सरकार देगी लेकिन किसान को 15 रुपये से कम नहीं देना होगा । ... (व्यवधान) ... मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं आज की बात नहीं कह रहा हूं । ... (व्यवधान) ...

श्री वीरेन्द्र वर्मा : 12.50 रुपये उत्तर प्रदेश में कीमत थी । आप क यहां क्या थ यह बतायें । गवर्नमेंट के मुकर्ररशुदा हिसाब से मैं कह रहा हूं ।

श्री भजन लाल : वर्मा जी, आपको अच्छी तरह से याद है, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं, बहुत पुराने आप मैंबर हैं, बड़े काबिल हैं और मेरे बड़ दोस्त हैं ।... (व्यवधान) ...

मैं भी स्टेट में 6 साल कृषि मंत्री रहा हूं । ये भी उत्तर प्रदेश में रहे हैं आपस में मिलते थे और हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं । वर्मा जी बहुत सुलझ हुए व्यक्ति हैं । बड़ी ठीक ब त कहते हैं और किसान के हित की बात कहते हैं । लेकिन वे इस बात को क्यों भूल जाते हैं, जब आदमी कुर्सी पर बैठ जाता है तो वह अपना जमाना भूल जाता है ।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO- As you now are.

श्री भजन लाल : दूसरों को बुरा भला कहने की कोशिश करता है । शीशे के महल में बैठकर दूसरों के ऊपर पत्थर फैंकना मुनासिब नहीं है । मुझे अच्छी तरह से याद है । कुछ किसान चौधरी चरण सिंह के पास इकट्ठे होकर गये । उन्होंने कहा कि हमें एक उद्घाटन करवाना है । चौधरी चरण सिंह सिर पर हाथ फेर कर कहने लगे कि किस चीज का उद्घाटन करवाना है । वे कहने लगे कि हमारे खेतों में गन्ना खड़ा है उसको आग लगानी है और इसका उद्घाटन आपसे करवाना है । बडे झुंझलाये चौधरी साहब । उन्होंने कहा कि मिलों तक उ को ले जाने के लिये 4 रुपया खर्च आता है जब कि मिल वाले 3.50 रुपये ही देते हैं । यह हालत थी । "गन्ना 4 लकड़ी 6, बोलो चरणसिंह की जै" लोग उस समय यह कहा करते थे । आपको शायद यह याद होगी ।

कपास और गन्ने की बीमारी के बारे में, उसकी रोकथाम के लिये सरकार पूरा इंतजाम करने पर लगी हुई है । किसी भी फसल पर कोई बीमारी न लगे इसकी हमारी कोशिश है । कपास और गन्ने पर बीमारी लगी थी उसकी हमने रोकथाम करने की कोशिश की है और अब शिकायतें भी कम आ रही हैं । हमारी पूरी कोशिश इस ब त की है कि बीमारियां न हों । सीड भी हम ऐसे पैदा कर रहे हैं जिसमें बीमारी

[श्री भजन लाल]

लगने की संभावना न हो । जहां पर बीमारी लग गई है उसके पूरे बंदोबस्त में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगा हुआ है ।

गरीबो हटाओ प्रोग्राम की बात इन्होंने कही । इसके लिये, आप जानते ही हैं कि करोड़ों रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है । पिछले एक साल में 15 सौ करोड़ रुपया हमने इसमें खर्च किया है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI IAGESH DESAI); You need not take all the points.

श्री भजन लाल : श्री कुलकर्णी जी ने एक बात यह कही कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 6 रुपया देते हैं तो नीचे एक रुपया पहुंचता है । उपसभाध्यक्ष महोदय, हम यह तो नहीं कह सकते कि एक ही रुपया पहुंचता है लेकिन यह ठीक बात है कि इसमें जरूर कहीं कुछ लेकुना है । अगर इसमें लेकुना है तो कुछ गड़बड़ी भी जरूर होती होगी । लेकिन जब तक कोई व्यक्ति पर्टिक्युलरी किसी के बारे में नहीं बताये कि फलां जगह फलां अधिकारी ने गड़बड़ी की है । इस तरह जनरल बात करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा । किस को पकड़ेंगे लेकिन फिर भी जो बात यहां पर आई है इसको चैक करेंगे और गहराई तक जाएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि भारत सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाए उसका सही इस्तेमाल उसी काम पर हो और पूरा पैसा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और पूरा फायदा गरीब आदमी को मिले ।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : (गुजरात) प्रधानमंत्री जी ने कई दफा कहा है ।

SHRI A. G. KULKARNI: I just wanted to draw the attention of the hon. Minister. He is an intellectual actually, an intellectual Agricultural Minister. What I said, Sir, is that it was the Prime Minister's observation about the total expenditure on bureaucracy, not that somebody took a single person has taken bribe. You referred to that. The adminstrative expenditure of the State or the Central Government is so high that out of Rs. 100/- spent only Rs. 16|- worth of development work takes place. So, the planning process has to be changed. So, please try to understand us.

श्री भजन लाल : : कुलकर्णी जी, बहुत पुराने, सीनियर मैम्बर है मैं उनकी इज्जत करता हूं । उनका बड़ा तजरबा है । लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूं कि आप जानते हैं कि सारा इम्पलीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट का है फिर मैं कहूंगा तो थोड़ी तकलीफ हो जाएगी । आप वेस्ट बंगाल को लें, आन्ध्र प्रदेश को लें जिस प्रोग्राम के लिए पैसा देते हैं उस पैसे को खर्च नहीं करते हैं । उसका नाम भी चेंज कर देते हैं । आन्ध्र प्रदेश में मुझे बताया गया कि जो हमने एन० आर०ई०पी० के लिए पैसा दिया उसका नाम तेलुगू देशम विकासम ग्रामीण कुछ इस तरह से (व्यवधान) बाकायदा उन्होंने क्या किया है, ग्रामीण सम्मेलन में किसी को बुला लिया, उप-समिति बना दी, किसी को रख दिया, वह जिस का नाम दे वह गरीबी रेखा से नीचे जिसका नाम नहीं दे वह गरीबी रेखा से नीचे नहीं । सारा काम पार्टी बेसेज पर चलाते है । उस पैसे का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं होता है । उस के लिए हम चैक करेंगे और जरूरी हुआ तो गाइडलाइस भी बदलेंगे । जो स्टेट गवर्नमेंट पैसे का ठीक इस्तेमाल नहीं करेगी उसके खिलाफ हम कार्यवाही भी करेंगे पैसा वापिस लेने की कोशिश करेंगे और पैसा देना बन्द करेंगे ताकि ठीक समय पर ठीक काम के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए ।

मूल्यों के बारे में कुलकर्णी जी ने सवाल उठाया । मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है । उन्होंने कहा कि फर्क है, शहरों में ज्यादा है और देहातों में कम है इसके बारे में मैंने चर्चा की है । डा० शिवाजी येलामनचिली ने किसानों के ऊपर लाठी चार्ज और आंसू गैस छोड़ी गई इसके बारे में कहा (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You need not go into that.

SHRl A. G. KULKARNI; A lot of statistics I supplied to him. Jf| ^tfT |

श्री भजन लाल : क्या चाहते हो आप ?

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : यह अखिल भारतीय ससद है । आप थोड़ा मगज में लें हम लोग क्या बोलें, उसका क्या मतलब है !

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl JAGESH DESAI): He is coming to it. Why do you hurry?

SHRl A. G. KULKARNI: I should wait.

श्री मुख्तियार सिह मलिक : आप एग्रीकल्चर की बात कह सकते हैं ! जो आपने अरबन डवलपमेंट और दूसरी सारी चीजों के बारे में सवाल उठाये उसका कैसे जवाब दे सकते हैं (**व्यवधान**) आल राऊड डवलपमेंट के बारे में कैसे बता सकते हैं (**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : जवाब मन्त्री जो देंगे या आप मलिक साहब ।

SHRl A. G. KULKARNI: It has gone over his head. Why should he be a Minister? Let him reply. I am asking him quesitons connected with agricut-ture, planning process, remunerative prices.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl JAGESH DESAI): Let us see what he replies.

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : आपका खुद का मैं बहुत आदर करता हूं ।

श्री भजन लाल : वह कोई बात नहीं मैं मानता हूं । जैसे आपने कहा कि कृषि के क्षत्र में वृद्धि के बारे में आपने जिक्र किया मैंने वृद्धि के बारे में पहले बताया कि उत्पादन का फर्क है । हर स्टट में एक जसा उत्पादन कहीं नहीं होता है सारे मुल्क में इसलिए फर्क रहेगा । आपने कहा कि शहरों में खर्च ज्यादा होता है देहात में कम होता है इसको हम मानते हैं कि शहरों में भी खर्च जरूरी है लेकिन देहात में जितना होना चाहिये मैं यह मान कर चलता हूं कि उतना नहीं हो रहा है । क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यह स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है । यह भारत सरकार का सारा सब्जक्ट नहीं है। भारत सरकार का काम पैसा देने का है । आगे पैसे को कसे खर्च करना है, कहां पर खर्च करना है यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है ।

SHRl A. G. KULKARNI: The farming community has come to its wits' end. You are waiting for a revolution now. Yon wa't for the revlution, then all these replies will come automatically.

श्री भजन लाल : मैं क्या कहूं कुलकर्णी जो आपको ।

SHRl A. G. KULKARNI: Mr. Vice-Chairman, you were there. You know what I spoke. It is not that I spoke something else. I am only requesting him that the conditions of farmers in this country have come to a boiling point. For heaven's sake you assure us that the Government will change the planning process, make more investment in the rural areas and meet the aspirations of the farmers. I gave you the instance how the interests on loans were rescheduled. You give us some assurance so that there is no Tikait or Sharad Joshi.

श्री भजन लाल : यहां पर जिक्र आया इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया था । मैं आपकी बात मानता हूं कि बाकायदा प्लानिंग में ठीक सुधार होना चाहिए । इसकी गाइडलाइंस मैंने आपसे अर्ज कर दी है । लेकिन इस बात की घोषणा मैं कैसे कर सकता हूं कि हम करेंगे । आपने अभी सुना नहीं ध्यान से, मैंने कहा था । दूसरी जो आपने बात कही कपड़ा नीति के बारे में कि इसको चेंज करना चाहिए तो इसके बारे में विचार करेंगे । जो सुझाव आपने दिये हैं उन पर विचार करेंगे कि क्या हो सकता

[श्री भजन लाल]

है । आपने कहा कि यार्न वगैरह इनका दे देते हैं इसलिए किसान की कपास मंदी हो जाती है, ठीक भाव में बिकती नहीं । सारी बातें मैंने नोट की हैं और हम सारी बातों पर विचार करेंगे और जो ठीक बात होगी वह करने की कोशिश करेंगे और इसी बात को लेकर किसानों के भले के लिए फूड प्रोसेसिंग की एक नयी मिनिस्ट्री प्रधान मंत्री जी ने बनायी है ताकि किसान को उसकी उपज का ठीक दाम मिल सके। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि फसल के टाइम पर बहुत मंदी हो जाती है, मिसाल के तौर पर अंगूर हैं उसकी सारी फसल एक महीने में खत्म हो जाती है । जब अंगूर की फसल आती है तो वह दो रुपये किलो में बिकता है और आजकल 20 रुपये किलो में भी नहीं मिलता । इसलिए प्रोसेसिंग करने का प्रोग्राम है ताकि किसान जो सारी चीजें पैदा करता है जैसे फल, सब्जी या दूसरी चीजें उसको उनका सही दाम मिल सके । इसलिए प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री चालू की है । इसी तरह से जैसे इन्होंने किसानों के बारे में कहा कि बहुत से किसान एक दिन के लिए यहां आकर धरना देकर बैठे गये । उनमें जो पानी का इंतजाम किया गया था तो टैंकर वापस नहीं जाने दिया जिससे झगड़ा हुआ और पुलिस वालों ने उनका पीटा उस बात पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका इससे इतना ताल्लुक नहीं है । इन्होंने कहा कि गांवों में, कस्बों में, बड़े-बड़े कस्बों में गोडाउन वगैरह होने चाहिए । एक सदस्य ने कहा कि पीने के पानी का इंतजाम देश में नहीं है । मैं इतनी बात कह सकता हूं कि देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना जब 31 मार्च, 1990 को खत्म होगी तो उस वक्त तक एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें पानी की व्यवस्था न हो । हर गांव तक 1990 में पीने का पानी पहुंच जायेगा । सिर्फ 3, 4 हजार गांव बाकी बचेंगे जो बहुत ऊंचे पहाड़ी एरिया में है या बहुत छोटे हैं, लेकिन बाकी इस देश में कोई भी गांव 1990 के बाद बगैर पानी के नहीं रहेगा । हर गांव में स्वच्छ और मुधरा पानी पहुंच जायेगा ।

सरदार दरबारा सिंह जी ने कहा कि औजार बनाने वाले लोगों का जैसे बढ़ई हैं, खाती है इन सब लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए । यह ठीक बात है । सरकार इनका ध्यान हमेशा रखती है लेकिन इनके बारे में और भी ध्यान देने की आवश्यकता है । दरबारा सिंह जी के बहुत अच्छे सुझाव हैं और इन्होंने खुद ही माना है इस बात को कि खाने वालों का ध्यान रखना चाहिए । एक इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत से लोगों ने जमीन दबाकर रखी है, कभी किसी कुत्ते के नाम कभी किसी बिल्ली के नाम । कौन पकड़े ? बड़ी समस्या है और मैं इतनी बात कह सकता हूं... (**व्यवधान**)

श्री दरबारा सिंह : अगर आप बिल्लियों और कुत्तों को ही नहीं पकड़ते तो... (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल : दरबारा सिंह जी मेरे बहुत पुराने और सीनियर साथी हैं, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे लेकिन मुश्किल क्या है, एक सवाल मैं दरबारा सिंह जी से पूछना चाहता हूं मुझे पूछने का तो अधिकार नहीं है क्योंकि मैं मंत्री हूं लेकिन जब ये मुख्य मंत्री थे तो क्या ये कुत्ते और बिल्ली उससे पहले के नहीं थे और ये खासकर पंजाब में ज्यादा हैं...

SHRI DARBARA SINC H; I would]ike to explain to him tl.at during thei time of the Akali party Government which was put up by some other people, not by the Congress, they irought up the ceiling upto 30 acres. It v as decided by them and this matter again went to the High Court and there they gave this decision that every person's son who is a major should also get 30 acres of land. What should we do ther:? The court has decided about it. But the point is that he could not do anj thing at that time in this matter.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : खैर इन्कम-टैक्स में तो जवान लड़के को मिल जाता है शहरी आमदनी में, किसान को नहीं मिलता है ।

श्री भजन लाल : काहे में ? उप-सभाध्यक्ष जी, सरदार दरबारा सिंह जी बहुत सीनियर मेम्बर हैं, मैं इनको कुछ कहता नहीं हूं । तीस एकड़ का भी था न--उनके पास तो हजार-हजार एकड़ आज भी होगी, तब भी थी ।

श्री ईश दत्त यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे एक मिनट का समय दें...(**व्यवधान**) मैं केवल एक मिनट ही लूंगा ।...(**व्यवधान**)

HE VICE-CHAIRMAN flSHRI JAGESH DESAI): What you want to do?

श्री भजन लाल : मैं तो वैसे ही कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने दबा रखी है । मैं अकेले पंजाब का जिक्र थोड़े कर रहा हूं, इसमें तो हरियाणा भी शामिल है ।

SHRI DARBARA SINGH: You could not. get hold of them at that time. T know everything.

श्री भजन लाल : मैं कोई उलझने की बात थोड़े ही करता हूं । मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूं कि कानून ऐसे हैं--मैंने खुद पहले कहा है कि लोग अदालतों में स्टे ले लेते हैं ।

श्री बीरेन्द्र वर्मा : पंजाब और हरियाणा में...(**व्यवधान**)

श्री भजन लाल : हरियाणा में बहुत बड़े जमींदार नहीं हैं पंजाब के मुकाबले में --हरियाणा में भी हैं, दो-चार घराने हैं, पर पंजाब में तो सैकड़ों घराने ऐसे हैं, जिनमें से पचास के नाम तो मैं यहां बता सकता हूं लेकिन यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि पंजाब और हरियाणा इकट्ठा रहा है । लेकिन एक बात और सरदार दरबारा सिंह जी ने बहुत अच्छी कही पानी के बारे में--बात बिलकुल ठीक है कि पानी और हवा दुनिया में सब की साझी है । इसको कोई दुनिया में बांध कर नहीं रख सकता ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : वह तो आपने बता दिया था ।

श्री भजन लाल : अब फिर सरदार साहब कहेंगे कि जब पानी का मामला आया, हरियाणा और राजस्थान के मामले में सरदार साहब सब से ज्यादा अड़े हुए थे कि हम नहर नहीं खोदने देंगे पानी हरियाणा को नहीं देंगे । आज कहते हैं, अच्छी बात है...(**व्यवधान**)

SHRI DARBARA SINGH: I have to reply to this question. The decision was taken by the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. Why you could not do it at that time? At that time, you were also the Chief Minister.

THE VICES-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Let us not go into that.

श्री भजन लाल : नहीं, मैं आपके बारे में नहीं, कह रहा हूं । मैं तो कहता हूं कि अच्छी बात है--मैं भी चीफ मिनिस्टर था, आपने पंजाब के हितों की रक्षा करनी थी और मैंने हरियाणा के हितों की रक्षा करनी थी । आज हम दोनों इससे ऊपर हैं । इन्होंने देश के बारे में ठीक बात कही है, इसमें कोई शक नहीं है ।

श्री दरबारा सिंह: मैंने यह कहा था कि चण्डीगढ़ जो है उसकी हिस्सेदारी-- I shall have to reply to that point. It is a part of that matter. On water, what a dispute he has created? I said it openly that Chandigarh doesi not belong to Punjab only. If this goes to Punjab, Haryana should be compensated. I said about this in this House and outside also. I took a right and reasonable stand; his Ministry and others have not taken that stand from Haryana.

श्री भजन लाल : मैं इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता हूं ।

श्री बीरेन्द्र वर्मा : माननीय दरबारा सिंह जी ने यह सुझाव दिया था कि सवाल बाद में पूछे लेंगे और बीच में ही बोल रहे हैं ।...(**व्यवधान**)

श्री भजन लाल : चलिये मैं इस बात को छोड़ता हूं और आगे चलते हैं ।

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): If I heard him aright, our Agriculture Minister said after his dialogue with Sardar Darhara Singh not to talk of 30 acres because* thousands of acres are already in many hands.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): What is your point of order?

PROF. SOURENDRA BHATTAy CHARJEE: My point of order is that if a Central Minister makes such a statement on the issues between the Centre and the States What is to be done to undo that situation or undo that position? *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI IAG-ESH DESAI): It is not a point of order.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE; It is very much a point of order. He was the Chief Minister. *{Interruptions).* What happend there at that time? *{Interruptions).*

श्री भजन लाल : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह स्टेट गवर्नमेंट का सब्जैक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट को बाकायदा इन्क्वायरी करके इनको सैक करना चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It is not a point of order.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE; It is a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAG-ESH RESAI): It is not a point or order. Please sit down. Argument is a different thing. *{Interruption)...* Please sil down.

श्री भजन लाल : दूसरा उप सभाध्यक्ष महोदय, कैलाश पति मिश्र जी ने कहा कि किसानों के जो बांध बगैरह के प्रोजेक्ट हैं वे जल्दी होने चाहिएं, ठीक है, इस बात को हम मानते हैं कि चाहे वे बिजली के प्रोजेक्ट हों या इरीगेशन के प्रोजैक्ट हों यदि भारत सरकार के हों तो जल्दी उनको स्वीकृत करना चाहिए । उसके लिए हम जरूर कहेंगे । एक उन्होंने कहा कि मूलधन से ब्याज ज्यादा हो जाता है, उसको मुआफ करना चाहिए । यह बड़ा वैलिड प्वायंट है । जहां सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए और किसान देने की स्थिति में नहीं हो वहां भारत सरकार ने फैसला कर दिया है प्रधान मंत्री जी ने बाकायदा आंध्र के अन्दर एनाउंस किया है और उसको हमने लागू कर दिया है । सब जगह बैंकों को हिदायतें कर दी हैं कि जहां तीन साल से ज्यादा सूखा पड़ गया दो साल से तीन साल उनकी बाकायदा किश्तें भी लंबी कर दी हैं कि 7 साल में, दस साल में वसूल करो । अगर रकम से ज्यादा ब्याज हो गया है तो वह सारा मुआफ हो जायेगा । उसको वसूल करने का सवाल नहीं है । अब यह कहते हैं कि बाकी भी मुआफ होना चाहिए । किन हालात में उसको मुआफ किया जाए । अगर ऐसे हालात हो जाएं कि सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तब तो ठीक है कि मुआफ होना चाहिए । लेकिन जब ली तो आदमी पैसा लेकर देता नहीं फिर उसका कैसे मुआफ हो सकता है । यह बहुत मुश्किल बात है । इसी तरह से गुजरात के बारे में बीमा योजना के बारे में है । ...(**व्यवधान**)

श्री **सोहन लाल धूसिया** (उत्तर प्रदेश) : आप सूखा वाले क्षेत्र में लेंगे या नहीं ? ...(**व्यवधान**)

श्री भजन लाल : अगर असल रकम से ज्यादा हो जायेगा तो ऊपर का सारा छोड़ देंगे । मेरी बात सुनिए अगर असली दस हजार रुपये लिया है और दस हजार सूद हो गया तो उसमें ऊपर का छोड़ देंगे । अगर ज्यादा होगा तो नहीं लेंगे ।

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): Sir, as far as electricity chargis are coa-cerned... *{Interruption')..*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAG-ESH DESAI): After a long time you are awake.

श्री भजन लाल : आप बाद में आए, बिजली का मैंने पहले जिक्र किया है । आपके आने से पहले मैंने डिटेल में बताया है कि 80 पैसे के हिसाब से बिजली घर में पड़ती है और 18 पैसे के हिसाब से देते हैं ।

SHRI N. E. BALARAM: No, no. You did not catch *my* point. I am not going in for that. The Minister has promised to do something. On that point, he is going to implement something. In Tamil Nadu, they are collecting not only back arrears but they are collecting back arreafc with compound interest. It is a very difficult problem. *(Interruptions).*

श्री भजन लाल : उप सभाध्यक्ष महोदय यह स्टेट अलग-अलग तय करके चार्ज करती है । यह स्टेट सब्जैक्ट है । भारत सरकार न उनको हिदायत दे सकती है और न उनको डाइरेक्शन दे सकती है क्योंकि वह स्टेट सब्जैक्ट है । जहां तक दीपे का ताल्लुक है वह बीमा योजना चालू है । कुछ गुजरात के किसानों का पैसा बकाया है वह बहुत जल्दी हम देने जा रहे हैं । बहुत जल्दी फैसला होने वाला है । इसी तरह से बाढ़ के बारे में है । उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि काफी हद तक हमने बाढ़ की रोकथाम की है और आगे भी हम करने जा रहे हैं ताकि देश में कम से कम बाढ़ आये । इसी तरह से इन्होंने टिड्डी दल के हमले के बारे में कहा । टिड्डी दल का कोई खास हमला नहीं हुआ और न ही टिड्डी दल आने की उम्मीद है । इसलिए ज्यादा डरने की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए । चतुरानन मिश्र जी ने कहा कि प्रधान मंत्री ने आन्ध्र में जो कहा था वह पूरा नहीं किया । वह सारी बातें पूरी की हैं । इसीलिए हमने एक नया मंत्रालय बनाया है ताकि प्रोसैसिंग का और रख-रखाव का इंतजाम ठीक हो । किसान की बीमा योजना में छोटे किसानों को कवर किया जाए । सारे किसानों को कर्जे मुआफ करने की बात है, कर्जे मुआफ करने का मैंने पहले कई दफा कहा है कि कुछ हद तक माफ किए जाते हैं, हर साल होते हैं । आप जानते हैं, जो कोई देने के लायक नहीं होते या दूसरे हालात हैं, उसके कुछ हद तक माफ किए जाते हैं । लेकिन सारे कर्जे कोई भी सरकार माफ नहीं कर सकती । सारे कर्जे माफ करने की बात होती तो पहले आंध्र प्रदेश वाले कर दें, वेस्ट बंगाल वाले कर दें, कर्नाटक वाले कर दें, फिर तो मान लें कि उन्होंने तो कर दिए, कांग्रेस वाले नहीं करते । सारे कर्जे माफ करना बड़ा कठिन काम है । सारे कर्जे तभी माफ होंगे जब सारा का सारा काम स्टेट का बंद करके इसकी तरफ आया जाये : अगर किसी को तसल्ली नहीं होती तो हरियाणा में जाकर के देखें, जहां देवी लाल जी ने कहा था कि सारे कर्जे माफ हो जाएंगे । एक किसान भी नहीं कहेगा कि मेरा कर्जा माफ हो गया है । ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : 240 करोड़ के माफ हुए हैं ।

श्री भजन लाल : ऐसे तो पता नहीं, कितनी बार कर रखा है । मगर माफ नहीं हुए ...(**व्यवधान**).. आप जानते हो कितने कर्जे राइट-आफ होते हैं साल में, जो देने के लायक नहीं हैं, उनके या देने वाला मर जाये या पीछे देने वाला कोई न हो तो राइट-आफ हो जाते हैं ।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andh ra Pradeh): On the other day also I mentioned that you might take inspiration from Pawar if not from Devi Lai.

THE VICECHAIRMAN (SHR1 JAGESH DESAI): Is there any othci- ma jor point remaining now?

श्री भजन लाल : मैं दस मिनट और लूंगा सिर्फ । एक बात सोलिंग के बारे में विकल साहब ने कही, मैंने जिक्र किया । दूसरे मुआवजे का जिक्र किया, वह मैंने अभी विकल साहब को जवाब दिया था । आपने यह कहा कि कीमतें कम देते हैं किसान को ...(**व्यवधान**)...

श्री राम चन्द्र विकल : मान्यवर, मैं तो दो ही बात चाहता हूं । आपने दो बार एलान किया, पहले भी और आज भी कि देश के हर हिस्से में जीप्स जा रहे हैं । इसको आप सत्य सिद्ध कर दें, रेडियो पर आप एलान कर दें । कहीं भी रोका जा रहा होगा तो मैं शिकायत लाऊंगा आपके पास । दिल्ली में ही आने पर पाबंदी है । दूसरा आप यह कह रहे थे कि हरियाणा में हमने यह कर दिया, मुआवजे देकर के जमीन

[श्री रामचन्द्र विकल]

दी जती है। इस पर अमल हो रहा है या नहीं? सिर्फ दो बातें आप कर दें तो मैं मान लूंगा।

श्री भजन लाल: देखिए, मेरे जमाने में... **(व्यवधान)**...

श्री राम चन्द्र विकल: मैं आज की बात कह रहा हूं। आपका जमाना भी उसमें जुड़ जायगा। किसान की जमीन बिना मुआवज के ली जा रही है या नहीं ली जा रही है? इसको आप तय कर दो देश भर में। दूसरे, जीन्स को चाहे जहां ले जाने की आजादी है या नहीं है?

श्री भजन लाल: ठीक है, विकल साहब, जो आपने सुझाव दिए हैं। एक तो मैं कह सकता हूं कि मूवमेंट में आज के वक्त कोई पाबंदी नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, कहीं राइटली प्रोक्योरमेंट के हिसाब से किन्हीं स्टेट गवर्नमेंट ने वैसे कहीं कुछ कर रखा तो बात दूसरी है, लेकिन कानूनी तौर से प्रदेश सरकार मूवमेंट पर बेन तब लगाती है, जब भारत सरकार कोई मंजूरी दे। भारत सरकार ने कोई मंजूरी किसी स्टेट को नहीं दी है कि वह पाबंदी लगाए और भारत सरकार की मंजूरी के बिना कोई बेन लग नहीं सकता।

श्री राम चन्द्र विकल: नहीं जी, दिल्ली के किसान हरियाणा में पलवल की साइड में फार्म लिए हैं, उनका गल्ला नहीं आने देते दिल्ली में।

श्री भजन लाल: विकल साहब, सेल्स टेक्स वगैरह चेक करते होंगे, टेक्स वगैरह का चैक होगा। वैसे परेशान करने की बात नहीं है। फिर भी हम भारत सरकार की तरफ से स्टेटों को लिखेंगे कि किसान को परेशान न किया जाये।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक: वह तो सिर्फ व्यापारी के गल्ले की चेक करते हैं।

श्री भजन लाल: टेक्स वगैरह चेक करते होंगे। मुआवजे के बारे में हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट को कि किसान को पहले मुआवजा दें, बाद में जमीन लें और मार्केट रेट उनको दें।

सरोजिनी साहिबी जी ने कुछ बातें कहीं कि किसान की हालत बहुत खराब है, लागत सीलिंग के बारे में भी और खाद के बारे में भी कहा एन०पी०टी० ज्यादा बढ़ गया, खाद में मिलावट है। इसको हम पूरा चेक करेंगे और पूरा चेक किया जाता है समय-समय पर ताकि किसान को अच्छा खाद और बीज मिले और किसी प्रकार की उसे कोई दिक्कत न हो। जल की सीपेज के बारे में बात आई, इसके बारे में हम कोशिश करते हैं कि नहरें पक्की बनें ताकि पानी की सीपेज कम हो। सीडस, बीज के बारे में मैंने आपको बताया।

नारायणसामी जी का कहना था कि बैंकों से कर्जे ठीक नहीं मिलते, किसानों को परेशानी है। इसको भी हम चेक करेंगे। पानी के बारे में मैंने जिक्र किया था। लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं, उसकी भी पहले मैंने आपके सामने चर्चा की है। बाढ़ के बारे में, सूखे के बारे में मैंने आपको बताया। एक मिसेज चक्रवर्ती जी ने कहा, वोट क्लब रेली के बारे में, मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। बाढ़ आसाम, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जो आई, भारत सरकार की तरफ से वहां जहां भी बाढ़ आई पूरी सहायता की

4.00 P.M. गई है। इसी तरह से हरी सिंह बाल्मिकी जी ने भी बहुत अच्छी बातें कहीं। छोटे किसानों के लिए एग्रो सर्विस सेंटर होने चाहिए। जो किसान छोटे हैं और ट्रैक्टर नहीं रख सकते, उनके लिए हम चाहते हैं कि उनकी काश्त करवायी जाए। हम बहुत वाजिब पैसा वसूल कर काश्त करवाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे और सीमांत किसानों की रक्षा करनी चाहिए। यह हो रही है। किसानों के भूमि सुधार की बातें आ गयीं। एक बात जो मटटू साहब ने कही, उसका मैं जिक्र जरूर करूंगा।... **(व्यवधान)**... मटटू साहब की बात का जवाब देकर मैं बठूंगा। उन्होंने कहा कि यह बताना चाहिए कि उत्पादन की क्या पोजीशन

है, आइल सीड की, पल्सेज की और अनाज की ? मैं यह बताना चाहता हूं कि 1987–88 में राइस की पैदावार हुई 48 और इस दफा हमारा लक्ष्य 67 मिलियन टन का है । लेकिन हम इस लक्ष्य को पार करके उम्मीद है कि 69.35 मिलियन तक पहुंचेंगे । इसी तरह से आपने दालों के बारे में कहा था । मैं बताना चाहता हूं कि 87–88 में जो हमारा उत्पादन था वह 110 लाख टन था और इस दफा हमारा टार्गेट था 133 लाख का और पैदा होंगी 157 लाख टन । इसी तरह से टोटल जो प्रोडक्शन होगा आइल सीड का 87–88 में 120 लाख टन पैदा हुआ और इस दफा 156.5 लाख टन । इसी तरह से सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी विचार किया गया है । एक आपने एडीबल आइल का जिक्र किया कि भाव गिर रहा है और बाहर से मंगा रहे हैं । इसके बारे में खाद्य मंत्री जी सोमवार को एक नयी पालिसी एनाउंस करेंगे और उस एनाउंसमेंट के बाद मैं समझता हूं कि किसान का जो आइल सीड है, उसके मुनासिब भाव भी किसान को मिलने लगेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत समय दिया और माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बड़ी शांति से सुना । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं । (**व्यवधान**)

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : यह बहुत इम्पोर्टेंट है, किसान का उस पर सारा दारोमदार है । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री भजन लाल : आप मुझसे बाद में पूछ लें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने विस्तार के साथ कृषि पर हुई चर्चा की डिबेट का उत्तर दिया । मैंने जो प्वाइंट्स उठाए थे उन सभी में जो बहुत महत्वपूर्ण थे उन पर उन्होंने चर्चा नहीं की । इसलिए मैं आपकी आज्ञा से दो-चार (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : दो-चार नहीं, सिर्फ दो ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : दो-तीन ही, हां वही मैं रख रहा हूं । पहली बात तो यह कि मैंने अनुदान की चर्चा की थी . . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप नोट कर लीजिए भजन लाल जी और बाद में जवाब दे दीजिए ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : भारत सरकार 22 सौ करोड़ रुपए खाद्यान्न पर अनुदान देती है और 18 सौ करोड़ रुपए फर्टिलाइजर्स पर अनुदान देती है । मैंने यह कहा था कि न किसान को अनुदान पहुंचता है, न उपभोक्ता को पहुंचता है और मैं यह प्रार्थना माननीय कृषि मंत्री जी से करूंगा कि अगर वह कष्ट कर सकें तो मेरे द्वारा दिए गए भाषण को बरबटिम पढ़ लें, जो मैंने कहा था कि खाद पर और खाद्यान्न पर जो भारत सरकार द्वारा सबसिडी दी जाती है वह न तो उपभोक्ता को पहुंचती है, न किसान को । मैंने एक सुझाव भी दिया था कि ऐसा करें जो डाइरेक्ट वह उपभोक्ता और किसान को मिले . . . (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल : मैंने कहा था, आप नहीं थे, दुबारा बताऊंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : दूसरी बात मैंने कही कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, ग्रामीण विकास कार्यों पर और सिंचाई पर 44.6 प्रतिशत खर्च किया गया था पहले प्लान में और सातवें प्लान में, जब कि प्लान बहुत बड़ा हो गया है, कृषि पर और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर और सिंचाई पर 21.7 प्रतिशत खर्चा है, आधे से भी कम हो गया है । इस पर आपने कोई चर्चा नहीं की ।

मैंने कहा था कि 40 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे इस देश में हैं । राष्ट्रीय आय का केवल एक फीसदी गरीबी की रेखा लोगों को ऊपर उठाने में खर्च कर रहे हैं । तो राष्ट्रीय आय का केवल एक फीसदी खर्च होगा तो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर कैसे उठेंगे ?

मान्यवर, इन्होंने गन्ने की बहुत बड़ी चर्चा कर दी, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन केवल इतना बता देना चाहता हूं

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

कि हमेशा उत्तर प्रदेश से क्योंकि रिकवरी भी उत्तर प्रदेश में अधिक है, उत्तरप्रदेश से हरियाणा में एक रुपया कम मन्ने की कीमत रहती थी लेकिन पिछले दो सालों में, इस सीजन में और इससे पहले सीजन में उत्तर प्रदेश से 3 रुपए अधिक हरियाणा कीमत दे रहा है । मेरी यह प्रार्थना है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी और दूसरी जगह से भी आप हरियाणा जैसी प्राइस किसानों को दिलवायेंगे और मान्यवर, आखिरी बात, जो माननीय विकल साहब ने कही थी वही कह कर समाप्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश, खाली उत्तर प्रदेश नहीं कह रहा कि स्टेट की बाउंडरी ही, एक जिले से दूसरे जिले में भी अनाज नहीं जाने देते, ये भी किसान के साथ घोर अन्याय है ।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Sir, the honourable Minister was saying thai all the assurances would be fulfilled and all the assurances would be kept. I am just specifically raising one or two assurances which he had given and which have not been implemented.

Sir, when he came to Andhra Pradesh, he promised that 20 per cent of the interest on loans taken by the cotton growers would be cancelled and the banks would be directed to do it within a week or ten days. But this has not been done up till now. I have asked the same question.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): That is enough. He has understood it. Please sit down.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO; Please allow me. I have raised this question when the Consultative Committee attached to the Minsitry of Agriculture was meeting. He said that it was before the Finance Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): All right. Please sit down.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: He also said that it would be im-plemented within a few days But that also has not been done up till now.

Another assurance is about the agricultural labour. A Central legislation was promised long ago and that legislation has not yet been brought forward till now in order to protect the rights of the agricultural labourers.

THE VICECHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): He will reply. Please sit down now. He has noted down the points.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO; Let him reply to these points so thai we will know where we stand.

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी से बहुत सफाई के साथ उत्तर दिया है, वे हमारे परम मित्र हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भूला नहीं हूं ।

उप सभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आपने जो प्रश्न पूछना है वह पूछिए, अब भाषण मत कीजिए । सीधे सवाल पूछिए. . . .

श्री राम नरेश यादव : इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जनता पार्टी के मुख्य मंत्री थे, तो वह भूल गए, मैं नहीं भूला हूं । मैंने तीन सवाल उठाए थे । एक तो किसानों को कर्जा लेने में बैंकों से बड़ी कठिनाई होती है, उसका कैसे हल हो, इसके लिए हमने एक सुझाव दिया था कि किसानों के पास जोत की वही दे दी जाए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : इसका जवाब उन्होंने दे दिया है । If you want to give any suggestions, you can give him in writing.

श्री राम नरेश यादव : मैंने सुझाव दिया था, विकल जी ने भी यह सवाल उठाया था कि दोनों सिस्टम खत्म होने चाहिएं ताकि किसानों को नुकसान न हो ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : श्रीमन, मैंने डिस्कशन में भाग नहीं लिया लेकिन जहां भी जिक्र किया जाता है वह किसान को रिम्यूनरेटिव प्राइस देने का

सवाल है । आनरेबल मिनिस्टर ने इस चीज का जवाब देते हुए ऐग्रिकल्चरल कास्टस एंड प्राइसेज कमीशन का जिक्र किया कि वह बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में उसका जिक्र करते हुए कह दिया कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं--एक ऐग्रिकल्चर का और दूसरी इंडस्ट्री का । उन्होंने कहा कि ऐग्रिकल्चर को दें तो गाड़ी का पहिया आगे नहीं जाता । मैं कहता हूं कि जो ऐग्रिकल्चर का पहिया है वह जमीन में गड़ा हुआ है और इंडस्ट्री का जमीन के उपर आया है । गाड़ी इसलिए नहीं चलती । मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि इंडस्ट्री की प्राइस को लगाने के लिए उसको आप 20 परसेंट का मुनाफा देते हैं, तब उसकी प्राइस फिक्स करते हैं, मैंने बीच में कहा भी था कि ऐग्रिकल्चर कास्ट एंड प्राइसेज कमीशन में पता नहीं किसानों के नुमाइंदे कैसे बैठे हुए हैं जिन्होंने गोबर की खाद का दाम 10 रुपए लगाया है जब कि मैंने 25 रुपए लिया है किसान होते हुए भी, तो मंत्री जी यह बता दें कि प्राइस लगाने के लिए किसान को आप कितना मुनाफा देते हैं ?

श्री ईश दत्त यादव : मेरा कृषि मंत्री जी से सीधा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने मंगलदेव विशारद कमेटी नियुक्त की थी और उसने जांच की और अपनी रिपोर्ट दी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े-बड़े फार्म हैं जिन पर कुत्ते, बिल्ली के फर्जी नाम दर्ज हैं । उनमें कांग्रेस आई के एक बुजुर्ग नेता भी है जिनका 400 एकड़ का फार्म मिर्जापुर में है जिसके बेटे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं । तो आज तक सरकार ने उस रिपोर्ट पर क्यों नहीं कार्यवाही की है ? क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि उसको कार्यान्वित करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश की जो जमीन फंसी हुई है, उस सरप्लस जमीन को गरीब लोगों को दिलाया जा सके ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GHSH DESAI): You need not answer all the questions. Whichever you want to answer, you give the answer.

श्री भजन लाल : उपसभाध्यक्ष महोदय, वीरेन्द्र वर्मा जी ने यह कहा कि खाद्यानों पर सबसिडी जो देते हैं वह 2200 करोड़ रुपए की देते हैं और खाद पर 1800 करोड़ की देते हैं, उन्होंने खाद के आंकड़े गलत बताए, खाद पर 3000 करोड़ देते हैं, इन्होंने आंकड़े कम दिए हैं पता नहीं किसानों के हित में दिए हों ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतय्या) पीठासीन हुए]

यह हमने इसलिए किया है कि उसमें कोई रास्ता नहीं निकलता है । इसलिए यह किया है कि जहां खाद बनती है उस जगह उसका हिसाब लगाकर, कम करके किसानों को दी जाए । वरना अगर पैसे की शक्ल में देंगे तो कैसे दे पायेंगे । वर्मा जी आप लिख कर सुझाव भेज दीजिए उन पर विचार किया जा सकता है ।

दूसरा, आपने खाद्यान्न के बारे में कहा । पी०डी०एस० (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन) सिस्टम को सही करके, सबसीडाइज्ड करके गरीब आदमी को खाने के लिए देना पड़ता है । अगर सबसिडाइज्ड नहीं करेंगे तो गरीब आदमी महंगे भाव पर चीज खरीद नहीं सकता और अगर महंगा लगायेंगे तो किसान को भाव ठीक नहीं मिलेंगे । सरकार को सरकारी खजाने से सबसिडाइज्ड करके गरीब आदमियों को सस्ती चीजें देनी पड़ती हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : 52 रुपये से ऊपर दे रहे हैं...

श्री भजन लाल : आपने कहा था कि प्लान में जो खर्चा रखा था पहले बहुत ज्यादा था अब कम हो गया है, 4-5 परसेंट हो गया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैंने कहा था पहले 21.7 था अब 4-5 परसेंट हो गया ।

श्री भजन लाल : किसी ने कहा था कि एक का दुगुना किसी काम का नहीं और सौ की सवाई बढ़िया है । यानि एक

[श्री भजन लाल]

का दुगुना हो गया तो एक ही फालतू होगा । अगर सौ का सवाई हो जायेगा तो सवा सौ हो गया । इसलिए इस वक्त जो बजट है देश का 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का कृषि पर खर्च हो रहा है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 40 हजार करोड़ रुपये । पहले क्या था 3 हजार करोड़ से शुरू हुआ था । इसी तरह से इस मुल्क में गरीबी की रेखा के नीचे जो है यानि जिनकी आमदनी 4800 से कम है उनकी संख्या 24 मिलियन है और जिनकी आमदनी 6400 से कम है उनकी संख्या 20 मिलियन है । होटल 44 मिलियन हैं । हमने फैसला किया है कि 20 मिलियन को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर हालत सुधारी जाये । उस के लिए बाकायदा स्कीम बनाई है --आई०आर० डी० पी०, एन० आर०डी०पी० आदि, पैसा देने की, काम देने की । पैसा उनको दिया जा रहा है ताकि उनकी हालत में सुधार किया जा सके ।

अभी उन्होंने कहा कि यू०पी० में कीमत ज्यादा थी और हरियाणा में कम थी । यह शायद भूल जाते हैं कि हरियाणा की नकल हमेशा यू०पी० ने की। यू०पी० की नकल हरियाणा ने नहीं की । जो तीन रुपये फालतू की बात है यह दूसरा सीड है, दूसरा गन्ना है । जो कि अरली है और अच्छा है । उसमें चीनी की मिकदार ज्यादा है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सी०ओ०जे० 64 है । तीन रुपये ज्यादा दे रहे हैं ।

श्री भजन लाल : हमारे यहां तीन रुपये फालतू रहता है । हमने हमेशा फालतू रखा है । यह बड़ोतरी भजन लाल की चलाई हुई है, देवी लाल की या किसी और की नहीं है ।

दूसरा आपने अनाज पर पाबन्दी के बारे में कहा । अनाज पर पाबन्दी भारत सरकार की तरफ से कहीं नहीं है । अगर कहीं है तो इसको हम चैक करेंगे और अगर ऐसा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे ।

तीसरी बात आपने कोटन के बारे में कही कि 20 दिन में कर्जा समाप्त हो जायेगा । मैंने कोई ऐसी बात आन्ध्र प्रदेश में नहीं कही । मैंने यह कहा था कि आन्ध्र में इसकी वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के लिए 20 हजार रुपये प्रधान मंत्री ने एनाउन्स किये थे । कुछ लोगों ने कहा कि पहुंचे नहीं है । मैंने कहा कि 20 हजार रुपए अगर नहीं पहुंचे तो 30 दिन के अंदर पहुंच जायेंगे । मैंने आते ही चैक किया और वह 20 हजार रुपये जिन लोगों ने आत्महत्या की थी उनके परिवारों को वह मिल गये हैं, पहुंच गये हैं ।

दूसरे राम नरेश यादव जी ने कहा कि बैंकों से कर्जा देने में कठिनाई होती है ।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: When did it reach?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRi H. HANUMANTHAPPA): He has said thai it has already reached. You are not following Hindi.

SHRT jMOTURU HANUMANTHA RAO: That is what I am asking. When did it reach? On the 27th October, he was telling me that it has not reached.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Minister, he wants to know when it has reached. He wants to know the dates.

श्री भजन लाल : आपने कहा है, कल आपको डेट भेज देंगे, डेट लिखकर भेज देंगे । यह बात मैं हाउस में कह रहा हूं, अगर मैं कोई गलत बात कहूंगा तो आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा देंगे ।

जहां तक बैंकों का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंकों को कर्ज देना चाहिए । इस संबंध में सीनियर सेक्रेटरीज की मीटिंग भी हुई है और

हम चाहते हैं कि इसको और सरल बनाया जाये ताकि आम आदमी को कर्ज लेने में कोई दिक्कत न हो। इसको हम चैक करेंगे ताकि आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

श्री मुस्तियार सिंह मलिक ने कहा कि मुल्क के दो पहिए होते हैं--कृषि और उद्योग। कृषि के बारे में मैंने आपको बताया है ... (व्यवधान) आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं लिख कर भेज दीजिये, मैं आपके पास लिख कर भेज दूंगा।

मैंने कहा कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। इसके साथ-साथ खेत में काम करने वाला मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर वह भी देश की रीढ़ की हड्डी है और रथ के दो पहिए हैं। भारत सरकार को खाने वाले गरीब आदमी का और पैदा करने वाले, दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी हम चाहते हैं कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाये ताकि किसान को अधिक पैसे मिल सके और किसानों की हालत ठीक रहे।

एक बात यह भी कही गई कि उद्योगों को 20 परसेंट मुनाफा देने की बात कही जाती है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, कभी-कभी तो वे 40 परसेंट भी मुनाफा लेते हैं और कई दफा फेल भी हो जाते हैं। उनका मार्केट में कम्पीटीशन होता है और उसमें वे अपना माल बेचते हैं। उसमें भारत सरकार उनकी मदद नहीं करती है। जहां तक किसानों को मुनाफा देने की बात है, हम किसानों को 12 परसेंट मुनाफा देने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि किसानों को 12 परसेंट मुनाफा मिलना चाहिए।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO Mr. Vice-Chairman, Sir, I asked along with this.. .*(Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please sit down.

श्री भजन लाल : यू० पी० के बारे में मंगलदेव विशारद कमेटी की बात कही गई है ... (व्यवधान) ...

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Please allow me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRi H-HANUMANTHAPPA); I am not allowing you, I said, I know you have spoken yesterday and today and now you want a third chance. Please sit down.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Sir, Central legislation for insuring agricultural labour was promised and it has not come. This is the question I am now asking. *(Interruptions).*

SHRi BHAJAN LAL: About crop insurance?

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO': It is about Cenlral legislation for insuring agricultural labour, which was promised. *(Interruptions).*

श्री भजन लाल : शायद वे कोप इंश्योरेन्स की बात कह रहे हैं, फसल बीमे की बात कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : यह फसल बीमे की बात नहीं है।

श्री भजन लाल : फसल बीमे की बात मैंने वहां पर कही थी और कहा था कि इसको हम बढ़ाने जा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : यह फसल बीमे की बात नहीं है।

श्री भजन लाल : लेबर के बारे में तो कानून बना हुआ है। कोई नया बनाने की बात हो या कोई खामियां हों तो आप लेबर मिनिस्ट्री को लिखकर भेज दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : परसों ही लेबर के बारे में कांफ्रेंस हुई है।

श्री भजन लाल : इन्होंने कमेटी का जिक्र किया है। जहां तक मैं समझता हूं इस संबंध में एक कमेटी बनी हुई है और कमेटी को कहेंगे कि शीघ्र अपनी रिपोर्ट दे।

श्री ईश दत्त यादव : मंगलदेव विशारद कमेटी के बारे में क्या स्थिति है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : उन्होंने इसका जवाब दे दिया है।

श्री भजन लाल : हम स्टट गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि वह इसको देखे कि मामला क्या है। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

WAREHOUSING CORPORATIONS(AMENDMENT) BILL, 1987.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM); Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Warehousing Corporations Act, 1962, be taken into considerations."

The Central Warehousing Corporation and sixteen State Warehousing Corporations have been set up so far under the Warehousing; Cotfc>oraitiam<s Adl, 1962. These corporations acquire and build warehouses at suitable places and also godowns for storage of agricultural produce, fertilizers and certain other items, both agricultural and industrial. Sir, the Warehousing Corporations Act, 1962 extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. At tha time of the enactment of the Act in 1962, entry 33 of the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution *to* which the Act is relatable was not made applicable to the State of Jammu and Kashmir. The entry has since been made applicable to the State of Jammu and Kashmir.

Government considers that the Ware-| housing Corporations Act should also I be extended to the State of Jammu and Kashmir. Extension of the Warehousing Corporations Act, 1962 to the State of Jammu and Kashmir would give that State two benefits. Firstly, the Central Warehousing Corporation which is a Central public sector corporation set up under the said Act, would be able to operate in the State. The second bene-.fit ig that the State Government would be able to set up its own State Warehousing Corporation, which Corporation could avail of the 50 per cent equity contribution being made by the Central Warehousing Corporation to the State Warehousing Corporations as per the provisions of this Act. The balance 50 per cent of the equity capital would be provided by the State Government.

The extension of the Act of Jammu and Kashmir would enable growth of warehousing facilities in the State which would help farming community to store their seasonal agricultural produce.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

The question was proposed.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, nobody can have any objection to the extension of this Act to the State of Jammu and Kashmir. We support it. But it does not end her$_e$ because the way the Warehousing Corporation has been functioning, there is much room to talk about. Warehouses are meant for storage of goods, everybody knows, just as homes are for the human-beings. The warehouses have got a vital role to play in the economy. Besides storage, they facilitate marketing and distribution. Now the question comes as to how far we have been able to achieve thesle objectives. Originally we had some warehouses in the port towns; other warehouses were run mainly by i Central Warehousing Corporation. There are also State-run warehouses. The warehouses which are mainly intended for storing foodgrains are also utilised by industrialists for storage of industrial pro-